शोध मंथन Vol. XI No.IV Oct.-Dec. 2020 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 7.760 (SJIF)

संवर्धित भारतः संपर्कित भारत

डॉ॰ राकेश राय
असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग,
श्री द्रोणाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
दनकौर (गौतमबुद्ध नगर)
ईमेल : drrakeshrai7@gmail.com

सारांश

भारत की विशेषता कृषि क्षेत्र है। सरकार की डिजीटल इंडिया पहल किसानों की अनेक योजनाओं के लिए लाभकारी साबित हो रही है। कृशि क्षेत्र की कुछ योजनाओं में शामिल हैं, 'एम किसान', 'किसान पोर्टल', 'किसान सुविधा ऐप', 'पूसा कृषि', 'सॉयल हैल्थ कार्ड ऐप', 'ईनाम', 'फसल बीमा मोबाइल ऐप', 'एग्री मार्केट ऐप' और 'फर्टिलाइजर मॉनीटरिंग ऐप'। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'निर्भय ऐप' और 'हिम्मत ऐप' जैसे एप्लीकेशन शुरू किए गए जिनका इस्तेमाल महिलाएं विपत्ति में पड़ने पर कर सकती हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अदालतों और न्याय प्रणाली के लिए भी ऐप हैं। प्रौद्योगिकी का विकास प्रगति की आधारशिला है और शताब्दियों में इसने समाज के कामकाज के तौर–तरीकों को बदला है। प्रौद्योगिकीय आविष्कारों ने मानव श्रम को कम करके, दक्षता लाकर और उत्पादकता बढ़ाकर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी है। चाहे शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी हो, मीडिया और सेवा क्षेत्र में डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा के लिए स्वचालित उपकरण क्यों न हो; समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रौद्योगिकी का लाभ मिल रहा है। भारत जैसे देश के लिए जहां परम्परागत धरोहरों का अचूक मिश्रण है और जो सबसे बड़ी 'युवा आबादी' के साथ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहां प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ समाज का चेहरा बदलने के विशाल अवसर हैं, हांलाकि देश ने आजादी के बाद अनेक दशकों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय अविष्कारों को लागू होते हुए देखा है। वर्तमान सरकार ने न केवल देश में डिजिटल क्रांति की प्रकिया में तेजी लाने के लिए उत्प्रेरक का काम किया है बल्कि देश में डिजीटल विभाजन में सेतु बन्धन का काम किया है। पिछले तीन वर्षों में न केवल डिजिटल प्रौद्योगिकी के अन्वेषण, कार्यान्वयन और उपयोग में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है बल्कि डिजिटलीकरण और उसके लाभों को निचले स्तर तक ले जाने और खासतौर से समाज के उन वर्गों तक पहुंचाने पर जोर दिया है जिन्हें कम विशेष अधिकार प्राप्त हैं। किसी भी समाज में शिक्षा की गुणवत्ता समाज की वास्तविक रचना की आधारशिला है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए, डिजिटल इंडिया की पहल ने समाज में शिक्षा के प्रसार में सुधार के लिए अनेक डिजिटल सेवाओं को एक साथ ला दिया है। चाहे प्राइमरी स्तर हो, सैकंडरी स्तर अथवा उच्च शिक्षा और अनुसंधान की सुविधा हो, इस क्षेत्र में विभिन्न डिजिटल

योजनाएं देश की शिक्षा प्रणाली में क्रांति ला रही हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के पास 'राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल', 'ई ग्रंथालय', 'राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क' आदि हैं। ये डिजीटल पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की तरफ देख रही हैं बल्कि वंचितों तक शिक्षा पहुंचा रही है जिससे डिजिटल क्रांति का इस्तेमाल समाज के सम्पन्न और वंचितों के बीच की खाई को कम करने के लिए किया जा रहा है।

डिजिटल तकनीक के मौजूदा विकास में भी इस भूमिका को सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रहने चाहिए। नयी तकनीक के साथ आने वाली चुनौतियों, जैसे– ऑटोमेशन से बेरोजगारी बढ़ने, डेटा सुरक्षा के खतरे, एक तरफा विकास के कारण आर्थिक और सामाजिक वंचना गंभीर होने तथा बदलते माहौल में सांस्कृतिक असंतुलन आदि– पर भी ध्यान रखा जाना चहिए।

प्रस्तावना

हालांकि भारत सॉफ्टवेयर की एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, फिर भी नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवाओं की उपलब्धता अभी भी अपेक्षाकृत कम है । 2006 में अनुमोदित राष्ट्रीय ई दृशासन योजना ने मिशन मोड परियोजनाओं और कोर आई सी टी बुनियादी सुविधा के माध्यम से एक सतत प्रगति की है, लेकिन देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और ई दृशासन में प्रभावी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है। विजन इस पहल को संवेग एवं प्रगति प्रदान करता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, उपकरणों, विनिर्माण और रोजगार के अवसरों को शामिल करने से समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। 21वीं सदी में भारत अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करेगा जहां सरकार और उसकी सेवाएं नागरिकों के दरवाजे पर उपलब्ध हों और लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव की दिशा में योगदान करें। इसका उद्देश्य आई टी की क्षमता को इस्तेमाल करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिणत करना है।

पिछले चार–पांच वर्षों में स्मार्ट फोन, तेज इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, करोड़ों नये बैंक खाते, लाभुकों के खाते में सीधा भुगतान, आधार, प्रधानमंत्री जन–धन योजना, डिजिटल लेन–देन, स्टार्ट अप, सेवाओं की बेहतरी जैसे कारकों ने देश की बड़ी आबादी के लिए समावेशी आर्थिक माहौल पैदा किया है। निर्धन और निम्न आय वर्ग के लोगों से लेकर छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्यमी तक डिजिटल प्रसार का लाभ उठा रहे हैं। अवसर, संसाधन, तकनीक, सेवा और सुविधा तक नागरिकों की असमान पहुंच हमेशा से हमारे सर्वांगीण विकास की राह में एक बड़ा अवरोध रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने समुचित रोजगार, सही वेतन–भत्ते, सस्ती स्वास्थ्य सेवा की सुलभता तथा आवश्यक ऋण की उपलब्धता की समस्याएं हैं। डिजिटल तकनीक इस अवरोध को उत्तरोत्तर पाट रही है। तकनीकी प्रसार के साथ आर्थिक विकास के आधार पर भारत समृद्धि की राह पर अग्रसर है, परंतु वर्तमान गति से संतुष्ट हो जाना उचित नहीं होगा। राष्ट्रीय जीवन में तकनीकी बेहतरी के साथ नवोन्मेष और दूरदृष्टि का भी तालमेल आवश्यक है। सूचना क्रांति में वैश्विक स्तर पर भारत का शानदार योगदान रहा है। यह डिजिटल बदलाव साल 2021 तक भारत की जीडीपी

में 154 अरब डॉलर का योगदान कर सकता है। आगामी चार वर्षों में जीडीपी में सीधे या बतौर सहायक इसकी हिस्सेदारी 50 से 60 फीसदी तक हो सकती है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन जैसे डिजिटल नवोन्मेषों का लगातार प्रयोग बढ़ रहा है।

डिजिटल तकनीक के मौजूदा विकास में भी इस भूमिका को सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रहने चाहिए। नयी तकनीक के साथ आने वाली चुनौतियों, जैसे– ऑटोमेशन से बेरोजगारी बढ़ने, डेटा सुरक्षा के खतरे, एकतरफा विकास के कारण आर्थिक और सामाजिक वंचना गंभीर होने तथा बदलते माहौल में सांस्कृतिक असंतुलन आदि– पर भी ध्यान रखा जाना चहिए।

प्रौद्योगिकी का विकास, प्रगति की आधारशिला

प्रौद्योगिकी का विकास प्रगति की आधारशिला है और शताब्दियों में इसने समाज के कामकाज के तौर–तरीकों को बदला है। प्रौद्योगिकीय आविष्कारों ने मानव श्रम को कम करके, दक्षता लाकर और उत्पादकता बढ़ाकर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी है। चाहे शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी हो, मीडिया और सेवा क्षेत्र में डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा के लिए स्वचालित उपकरण क्यों न हो; समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रौद्योगिकी का लाभ मिल रहा है। भारत जैसे देश के लिए जहां परम्परागत धरोहरों का अचूक मिश्रण है और जो सबसे बड़ी 'युवा आबादी' के साथ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहां प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ समाज का चेहरा बदलने के विशाल अवसर हैं, हांलाकि देश ने आजादी के बाद अनेक दशकों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय अविश्कारों को लागू होते हुए देखा है। वर्तमान सरकार ने न केवल देश में डिजिटल क्रांति की प्रकिया में तेजी लाने के लिए उत्प्रेरक का काम किया है बल्कि देश में डिजीटल विभाजन में सेतु बन्धन का काम किया है। पिछले तीन वर्षों में न केवल डिजिटल प्रौद्योगिकी के अन्वेषण, कार्यान्वयन और उपयोग में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है बल्कि डिजिटलीकरण और उसके लाभों को निचले स्तर तक ले जाने और खासतौर से समाज के उन वर्गों तक पहुंचाने पर जोर दिया है जिन्हें कम विशेष अधिकार प्राप्त हैं। भारत में डिजिटल क्रांति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने समाज के लगभग सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कायापलट की है। वर्तमान सरकार की डिजीटल इंडिया पहल के साथ शासन प्रणाली से लेकर बेहतर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सेवाओं में डिजिटलीकरण, कैशलैस अर्थव्यवस्था और डिजीटल लेन–देन, अधिकारी तंत्र में पारदर्शिता, कल्याणकारी योजनाओं का निष्पक्ष और तेजी से वितरण जैसे लक्ष्य प्राप्त होते दिखाई दिए हैं। पिछले तीन वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की पहलों पर अगर नज़र डाली जाए तो पता लगता है कि किस प्रकार से भारत में डिजिटल क्रांति ने न केवल समाज के कामकाज के तौर तरीकों को बदला है बल्कि देश के साधन सम्पन्न लोगों और वंचितों के बीच की खाई को पाट दिया है।

भारत नेटवर्क (Bharat Network)

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (National Optical Fibre Network& NOFN) जिसे अब भारत नेटवर्क (Bharat Network) कहा जाता है, का उद्देश्य 40,000 करोड़ रुपए से अधिक

की लागत के साथ देष की सभी 2,50,000 पंचायतों को आपस में जोड़ना है। Bharat Net के माध्यम से सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 100 Mbps बैंड विड्थ प्रदान करने की परिकल्पना करती है ताकि ऑनलाइन सेवाओं को ग्रामीण भारत के सभी लोगों तक पहुँचाया जा सके।इसमें ई–गवर्नेंस, ई–लर्निंग, ई–बैंकिंग, ई–कॉमर्स और ई–स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं।इस नेटवर्क को स्थापित करने का कार्य पूरा हो जाने के बाद यह अवसंरचना न केवल एक राष्ट्रीय संपत्ति बन जाएगी तथा बल्कि गैर–भेदभाव पूर्ण पहुँच सेवा वितरण के माध्यम से यह नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास की दिशा में एक गेम चेंजर भी साबित होगी।

अभिभावकों और शिक्षकों का प्रशिक्षण

अधिकांश शिक्षक और अभिभावक तकनीकी रूप से दक्ष नहीं हैं और उनमें से कई तो ऐसे हैं जिनके पास तकनीक के बारे में बुनियादी ज्ञान का भी अभाव है। ऐसे में यह बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि उन्हें इस विषय में प्रारंभिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए ताकि वे अपने बच्चों को भी शिक्षित कर सकें। एक अन्य चुनौती यह है कि लॉकडाउन की समाप्ति के बाद जब अभिभावक अपने कार्यों पर लौट जाएंगे तब हज़ारों बच्चों को स्कूलों से बाहर रखना, चिंता का विषय है। ऐसे में यह समस्या उत्पन्न होगी कि इन बच्चों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी होगी और ये घर पर कैसे सीखेंगे।

इंटरनेट तक पहुँच में वषद्धि करना

कोरोना महामारी ने हमें नए और रचनात्मक तरीकों में बदलाव के साथ समायोजन स्थापित करने के विषय में बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन इस मार्ग में अपेक्षित एवं कमज़ोर वर्गों को साथ लेकर चलना भी उतना ही आवश्यक है, जितना कि तकनीक और विज्ञान को जीवन के नए आयामों में समाहित करना। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में रचनात्मक एवं तकनीकी पक्ष को शामिल करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिये, विशेष रूप से कम आय वाले समूहों से आने वाले सामान्य एवं निशक्त छात्रों की उपस्थिति के लिये यह बहुत महत्त्वपूर्ण है।

सरकार द्वारा शिक्षकों का डिजिटलीकरण करने के साथ–साथ बच्चों को ऑन लाइन शिक्षा के ऐसे प्लेटफॉर्म और अध्ययन सामग्री को निशुल्क उपलब्ध कराने पर बल देना चाहिये। उन्हें स्मार्ट फोन और लैपटॉप जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिये ताकि वे ऑनलाइन शिक्षा के दौर में मात्र आवश्यक बुनियादी ढाँचे के अभाव के चलते पीछे न रह जाए।

स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन प्रणाली का डिजिटलीकरण

शिक्षा का क्षेत्र समाज की रचना का निर्माण करता है, स्वास्थ्य सेवा भी समाज के लिए एक उतना ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसका सुरक्षित और स्थिर भविष्य है। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार की विभिन्न डिजिटल पहल में शामिल हैं– 'डिजिटल एम्स' एक ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य यूआईडीएआई और एम्स के बीच प्रभावी सम्पर्क बनाना; 'ई–अस्पताल' योजना जो स्वास्थ्य प्रबंधन योजना का एक खुला स्रोत है; 'एमरक्तकोष'– एक वैब आधारित तंत्र जो सभी सरकारी ब्लड बैंकों को एक नेटवर्क से जोड़ देता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा वर्तमान सरकार ने शासन प्रणाली के डिजिटलीकरण के लिए विभिन्न पहलें की हैं। उदाहरण के लिए

'उमंग' का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं; 'ई–पंचायत', 'ई–जिले', ई–कार्यालय के लिए एक ही जगह पर समाधान देना है। ये कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो देश में शासन और प्रशासन का डिजिटलीकरण कर रही हैं। इनके अलावा 'राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल' और 'ईसीआई–ईवीएम ट्रैकिंग सेवा भी षासन में पारदर्शिता लाने के लिए है। आधार योजना और भीम ऐप ने भी अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

डिजीटल इंडिया पहल

भारत की विशेषता कृषि क्षेत्र है। सरकार की डिजीटल इंडिया पहल किसानों की अनेक योजनाओं के लिए लाभकारी साबित हो रही है। कृषि क्षेत्र की कुछ योजनाओं में शामिल हैं, 'एम किसान', 'किसान पोर्टल', 'किसान सुविधा ऐप', 'पूसा कृषि', 'सॉयल हैल्थ कार्ड ऐप', 'ईनाम', 'फसल बीमा मोबाइल ऐप', 'एग्री मार्केट ऐप' और 'फर्टिलाइजर मॉनीटरिंग ऐप'। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 'निर्भय ऐप' और 'हिम्मत ऐप' जैसे एप्लीकेशन शुरू किए गए जिनका इस्तेमाल महिलाएं विपत्ति में पड़ने पर कर सकती हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अदालतों और न्याय प्रणाली के लिए भी ऐप हैं। देश में अभी आर्थिक मंदी पर बड़ी बहस चल रही है। निवेशक और एक्सपर्ट्स इस बात का आकलन कर रहे हैं कि इस मंदी का प्रभाव कब तक और कितना हो सकता है। इससे अलग डिजिटाइजेशन एक ऐसा साकारात्मक पहलू है जो लॉन्ग टर्म में देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हो सकता है।

बैंको के लिए डिजिटाइजेशन होगा फायदेमंद

डिजिटाइजेशन से क्रेडिट डिलिवरी सिस्टम बेहतर होगा। बॉरोअर्स के बारे में जानकारी कम होने की वजह से कई बार बैंक लोन देते समय कई जरूरी सावधानी नहीं बरत पाते हैं और उनका पैसा डूब जाता है। डिजिटाइजेशन के बाद बैंको के पास बॉरोअर्स के बारे में आवश्यक डेटा होगा, इससे लोन देते समय सावधानी बरती जा सकेगी। इससे लोन डूबने की संभावना कम रहेगी। अभी बैड लोन की वजह से अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जुलाई में लागू हुए जीएसटी की वजह से देश में बिजनस करने वालों के लिए टैक्स सिस्टम ज्यादा पारदर्शी हुआ है। इससे निवेश बढ़ेगा और नौकरियां बढ़ेंगी। ऑनलाइन जीएसटी की वजह से सरकार के लिए टैक्स वसूलने की समस्या काफी हद तक आसान हो गई है। सरकार को पहले के मुकाबले ज्यादा टैक्स मिलने का अनुमान है। यह फैक्टर लॉन्ग टर्म इकनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर साबित होगा गेमचेंजर

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा ने सरकार को काफी फायदा पहुंचाया है। अब सरकारी योजनाओं की सब्सिडी सीधे लोगो के खाते में जा रही है। कैश और चेक से अब पेमेंट नहीं हो रहा है। इसने बिचौलियों को खत्म किया है और भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम लगी है। सरकार के पास अब पहले से ज्यादा फंड होगा और इससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी।

एफडीआई बढ़ाएगा विकास की रफ्तार

भारत में हुए अलग–अलग आर्थिक सुधारों की वजह से अगले कुछ सालों में बड़ी मात्रा

में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने की संभावना है। एक्सपट्र्स का अनुमान है कि अगले 10 सालों में देश में एफडीआई अभी की तुलना में दो गुना हो जाएगा। नए जॉब्स क्रिएट होंगे, प्रति वयक्ति आय बढ़ेगी। एफडीआई देश के अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले सालों में पावर बूस्टर का काम करेगा। बीते तीन दशकों में हमारे देश में उदारीकरण की प्रक्रिया को व्यापक और सुगम बनाने में सूचना तकनीक का प्रमुख योगदान रहा है। अगले साल तक इस उद्योग का आकार 250 अरब डॉलर होने की संभावना है। माइक्रोसॉफ्ट और आइ डी सी एशिया–पैसिफिक की साझा रिपोर्ट का आकलन है कि यह डिजिटल बदलाव साल 2021 तक भारत की जीडीपी में 154 अरब डॉलर का योगदान कर सकता है। आगामी चार वर्षों में जीडीपी में सीधे या बतौर सहायक इसकी हिस्सेदारी 50 से 60 फीसदी तक हो सकती है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन जैसे डिजिटल नवोन्मेषों का लगातार प्रयोग बढ़ रहा है। तकनीकी प्रसार के साथ आर्थिक विकास के आधार पर भारत समृद्धि की राह पर अग्रसर है, परंतु वर्तमान गति से संतुष्ट हो जाना उचित नहीं होगा। राष्ट्रीय जीवन में तकनीकी बेहतरी के साथ नवोन्मेष और दूर दृष्टि का भी ताल मेल आवश्यक है। सूचना क्रांति में वैश्विक स्तर पर भारत का शानदार योगदान रहा है।

सरकार ने आई टी के ज़रिए शुरू की कई योजनाएं–

सरकार ने किसान कॉल सेंटर, ई–चौपाल, किसान चौपाल, ग्रामीण ज्ञान केंद्र , ई–कृषि, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी कई योजनाओं की आई टी के ज़रिए शुरुआत की है।

किसान कॉल सेंन्टर

सरकार ने किसान कॉल सेंटर की शुरुआत ऐसे किसानों को ध्यान में रखकर की जो सूदूरवर्ती गाँव में रहते है और वहीं बैठे खेती से संबंधित जानकारी चाहते हैं – जैसे– कृषि उत्पादकता कैसे बढ़े, उन्नत खेती के तरीके और उससे लाभ कैसे मिले। किसान कॉल सेन्टर के माध्यम से मुफ्त फोन सेवा (18001801551) व मैसेज से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।जैसे किसानों की समस्याएं, मौसम से संबधित जानकारी स्थानीय भाषा में नियमित रूप से दी जाती है।

ई चौपाल

ई चौपाल को किसानों को दलालों और विचैलियों से बचाने के लिए शुरू किया गया। इस में कृषि संयत्र, मौसम, फसल, कृषि उत्पादों की खरीद ब्रिकी, इंटरनेंट के ज़रिए किसानों को सीधे जोड़ा जाता है और उससे संबंधित सूचना दी जाती है। ई चैपाल से किसान अपनी उपज ऑनलाइन मंडी के द्वारा उच्च लागत से बेचते है जिससे उनको शुद्ध मुनाफा मिलता है ICT द्वारा किसानों को उनके उत्पादों की गुणवता में सुधार करने में मदद करता है। ई0 चैपाल सेवा शुरू होने के बाद से किसानों के उत्पादन की गुणवता तथा पैदावार में वृद्धि सुधार की वजह से उनके आय के स्तर में वृद्धि, और लेन देन में गिरावट आयी है।

किसान चौपाल

किसान चौपाल को कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK) चलाता है। कृषि वैज्ञानिक किसानों की

जरूरत को आंकलन के आधार पर किसान चौपाल गाँव में आयोजित की जाती है। किसान चैपाल में किसानों के खेती, फसल उत्पादन, पषु पालन एवं इससे संबधित समस्याओं को सुना जाता है और वीडियो, पावर प्वाइंट प्रजंटेषन, ऑडियो के ज़रिए उन्हें सुलझाया जाता है।

ग्रामीण ज्ञान केन्द्र

ग्रामीण ज्ञान केन्द्र, कृषि क्षेत्र में उपलब्ध जानकारी को किसान तक पहुंचाने, फसल उत्पादन से विपणन के लिए शुरू कर सूचना के प्रसार केन्द्र के रूप में कार्य करता है। जिसके माध्यम से कृषि, बागवानी, मत्स्य, पशुधन, जलसंसाधन, टेलीस्वास्थ, जागरूकता कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, कंप्यूटर शिक्षा तथा आजीविका सहायता के लिए कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड

यह योजना भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने षुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देष्य किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना है।वैसे किसान जिन्हें बार–बार कर्ज़ के लिए बैंकों के पास जाना पड़ता था, और बार– बार बैंकिग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था जिससे किसानों को जरूरत के समय कर्ज़ नहीं मिल पाता था। किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण किसानों को समय से मिल जाता है और खेती में नुकसान होने पर रकम अदायगी के लिए अवधि में असानी से बदला जा सकता है, जिससे किसानों को अधिक परेषानी भी नहीं होती है और अतिरिक्त बोझ भी नही पड़ता है।

कोरोना वायरस महामारी के कारण शिक्षा क्षेत्र इस समय गंभीर संकट का सामना कर रहा है। COVID–19 के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और संभवतः वे दिसंबर 2020 तक बंद रहेंगे। यदि स्थितियाँ ज्यों की त्यों बनी रहती है तो शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्णय वर्ष 2021 तक भी विस्तारित हो सकता है। इस स्थिति में शिक्षा को संचालित रखने के लिये ऑन लाइन शिक्षा प्रणाली पर फोकस किया जा रहा है। हालाँकि ऑन लाइन शिक्षा प्रणाली के संचालन में बहुत सी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से वर्तमान स्थिति में इन में जल्द से जल्द सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

डिजिटल शिक्षा की चुनौतियाँ

1.उचित अध्ययन स्थानों का अभाव

वर्ष 2011 की जन गणना के अनुसार, तीन या उससे अधिक सदस्यों वाले 71 प्रतिशत घरों में दो कमरे या उससे भी कम (74 प्रतिशत ग्रामीण और 64 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में) आवासीय स्थान हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को पढ़ने के लिये अलग से स्थान उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य साबित हो रहा है।

2.इंटरनेट की अपर्याप्त पहुँच

वर्ष 2017–18 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Survey) के आँकड़ों के अनुसार, केवल 42 प्रतिशत शहरी और 15 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा मौजूद थी और केवल 34 प्रतिशत शहरी एवं 11 प्रतिशत ग्रामीण व्यक्तियों ने पिछले 30 दिनों

में इंटरनेट का उपयोग किया था। ये आँकड़े स्पष्ट रूप से इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के संचालन में स्वभाविक रूप से कम से कम दो तिहाई (2/3 तक) बच्चे ऑन लाइन शिक्षा प्रक्रिया के दायरे से बाहर हो जाएंगे। हमेशा की तरह इस प्रक्रिया में भी सबसे अधिक प्रभावित हाशिए पर मौजूद, ग्रामीण और गरीब आबादी ही होगी।

3.इंटरनेट की धीमी गति

जब ऑनलाइन शिक्षा की बात आती है तो इसका अर्थ इस बात से होता है कि शिक्षकों के साथ सीधे वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद स्थापित किया जाए या ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से व्याख्या न दिये जाएं। दोनों कार्यों के लिये एक स्थिर, हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। इंटरनेट की पर्याप्त गति के अभाव में ऑनलाइन शिक्षा का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इस दिशा में हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू–कश्मीर के छात्रों द्वारा किये जा रहे नियमित विरोध प्रदर्शन को देख सकते हैं। इसका कारण यह है कि उचित इंटरनेट कनेक्शन के अभाव में वे अध्ययन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं।

निष्कर्ष

डिजिटल शिक्षा सभी संवर्गों के लिये शिक्षा का एक आनंद दायक साधन है। विशेष रूप से बच्चों के सीखने के लिये यह बहुत प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है क्योंकि मौलिक ऑडियो–वीडियो सुविधा बच्चे के मस्तिष्क में संज्ञानात्मक तत्त्वों में वृद्धि करती है, बच्चों में जागरूकता, विषय के प्रति रोचकता, उत्साह और मनोरंजन की भावना बनी रहती है। वे सामान्य की अपेक्षा अधिक तेज़ी से सीखते हैं। डिजिटल लर्निंग में शामिल INFO&TAINMENT संयोजन इसे हमारे जीवन एवं परिवेश के लिये और अधिक व्यावहारिक एवं स्वीकार्य बनाता है। डिजिटल लर्निंग को छात्र एक लचीले विकल्प के रूप में देखते हैं जो उन्हें अपने समय और गति के अनुसार अध्ययन करने की अनुमति देता है। शिक्षकों को भी तकनीकी के सहयोग से अपनी अध्यापन योजना को बेहतर बनाने में सुविधा होती है, साथ ही नवाचार एवं नए विचारों के समावेशन से वे छात्रों को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित भी कर पाते हैं। शिक्षण में तकनीकी के प्रवेश से यह एनीमेशन, गैमिफिकेशन और विस्तृत ऑडियो–विज़ुअल प्रभावों के मिश्रण के साथ और अधिक प्रभावी एवं तेज़ी से ग्रहण करने योग्य हो जाता है।

इसलिये शिक्षण और अधिगम के ऑनलाइन उपाय निश्चित तौर पर प्रशंसा के पात्र हैं, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब उन्हें उचित माध्यम से स्थापित किया जाए, स्पष्ट रूप से इन उपायों को फेस–टू–फेस शिक्षा की पद्धतियों के पूरक, समर्थन और प्रवर्धन के रूप में स्वीकार्य बनाया जाने पर बल दिया जाना चाहिये।

सुझाव

डिजिटल तकनीक के मौजूदा विकास में भी इस भूमिका को सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रहने चाहिए। नयी तकनीक के साथ आने वाली चुनौतियों, जैसे– ऑटोमेशन से बेरोजगारी बढ़ने, डेटा सुरक्षा के खतरे, एक तरफा विकास के कारण आर्थिक और सामाजिक वंचना गंभीर होने तथा बदलते माहौल में सांस्कृतिक असंतुलन आदि– पर भी ध्यान रखा जाना चहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1– योजना, दिसंबर 2019 पृ ० **37**

2– दैनिक समाचार ,संपादकीय पेज 23 फरवरी 2020

3-https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_India

4-https://hi.wikipedia.org/wiki

5-https://navbharattimes.indiatimes.com/india/digital-india-programme-details-in-hindi/articleshow

6-https://www.india.gov.in/hi/spotlight

7-https://www.hindikiduniya.com/essay/digital-india-essay-in-hindi/